

प्रेषक,

संयुक्त सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2015

विषय-राजकीय कर्मियों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न श्रेणी के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराये का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय कालोनियों के आवासों एवं विधायक निवासों के आवासों के किराये का पुनर्निर्धारण राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- आर-73/32-2-2014-21/2001, दिनांक-03, जून, 2014 के द्वारा किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-7003/32-2-2001-27/2001, दिनांक-11.01.2002 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न श्रेणी के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन का क्षतिपूर्ति किराया श्रेणी-1, 2 व 3 के आवासों के लिये प्रतिमाह रू० 20.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया की निर्धारित दर को बढ़ा कर प्रतिमाह रू० 40.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया तथा शेष अन्य आवासों के लिये प्रतिमाह रू० 25.00 प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर को बढ़ाकर रू० 50.00 प्रतिमाह प्रतिवर्ग मीटर किया गया है।

3- राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अनुरक्षण एवं अन्य मदों पर होने वाले भारी व्यय को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराये का भी पुनर्निर्धारण किया जाये। प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराया को संशोधित करते हुये निम्नवत् क्षतिपूर्ति किराया पुनर्निर्धारण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राज्य सम्पत्ति विभाग के श्रेणी-1, 2 व 3 के आवासों के लिये प्रतिमाह रू० 40.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया की निर्धारित दर को बढ़ा कर प्रतिमाह रू० 80.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया तथा शेष श्रेणी-4 से 6 तक के आवासों के लिये प्रतिमाह रू० 50.00 प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर को बढ़ाकर रू० 150.00 प्रतिमाह प्रतिवर्ग मीटर किया जाता है।

कैम्प मुख्य अभि० (भवन)
हायरी सं० 66 दिनांक 22/1/15

5E100/5E390/5E799

22/1

(आर० सी० बरनवाल)
मुख्य अभियन्ता (भवन)
लॉन्नि०वि०, लखनऊ

कैम्प-प्र०अनि०(परि०नियो०)

हायरी सं० 239311 दिनांक 22/1/2015

264G

27-1-15

शु० अग्रि० (भवन)

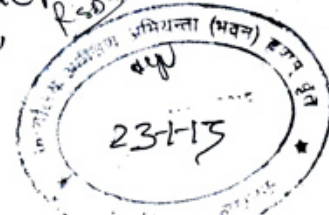
23-1-15

Sr. Manoj Kumar

FWD

web site

23-1-15



E.C.

- 2- इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक-11.01.2002 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेगी। उक्त क्षतिपूर्ति किराया आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
- 3- उक्त शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-218/दस...5 दिनांक-20-1-2015...में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

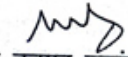
बृजराज सिंह रादव
संयुक्त सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या:- आर-457 (1)/32-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नगर विकास मंत्रालय(सम्पत्ति निदेशालय) नई दिल्ली।
- 3-लखनऊ स्थित भारत सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।
- 4-राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक।
- 5-निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
- 7-उ०प्र० समस्त मंत्री गण के निजी सचिव/सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
- 8-मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर/सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9-प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10-अधीनस्थ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11-सचिवालय के समस्त अनुभाग/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
- 12-स्थानिक अधिकारी, कोलकाता।
- 13-विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- 14-वित्त(समान्य) अनुभाग-1(तीन प्रतियों में)
- 15-वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
- 16-राज्य सम्पत्ति विभाग के समस्त व्यवस्थाधिकारी।
- 17-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सुधीर कुमार रूंगटा)
सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी।